<u>समक्ष उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>विशेष अपील संख्या 1020/ 2018</u>

एम/ एस नेक्टर लाइफ साइंसेज .....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ...प्रतिउत्तरदाता

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री एस.के.पोस्टी।

श्री मोहित मौलेखी, राज्य के विद्वान स्थायी वकील।

साथ

<u>विशेष अपील संख्या 54/ 2014</u>

मेसर्स इंड स्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड और अन्य .....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ... प्रतिउत्तरदाता

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री एस.के.पोस्टी।

श्री मोहित मौलेखी, राज्य के विद्वान स्थायी वकील।

साथ

<u>विशेष अपील संख्या 1018/ 2018</u>

मैसर्स के.वी. एरोमेटिक्स अपने निदेशक के माध्यम से

शुधांशु अग्रवाल .....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य (वित्त)

संस्थान और वित्त ... प्रतिउत्तरदाता

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री एस.के.पोस्टी।

श्री मोहित मौलेखी, राज्य के विद्वान स्थायी वकील।

साथ

विशेष अपील संख्या 1019/ 2018

मैसर्स अभय केमिकल्स .....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य (वित्त)

संस्थान और वित्त ... प्रतिउत्तरदाता

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री एस.के.पोस्टी।

श्री मोहित मौलेखी, राज्य के विद्वान स्थायी वकील।

दिनांक: 19 मार्च, 2019

कोरम: माननीय रमेश रंगनाथन, सी.जे.

माननीय एन.एस. धनिक, जे.

रमेश रंगनाथन, सी.जे. (मौखिक)

ये चार विशेष अपीलें सिविल विविध रिट याचिका संख्या 1921/2013 दिनांक 9.1.2014 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं। ग्यारह अलग-अलग करदाताओं ने 2013 की सिविल विविध रिट याचिका संख्या 1921 में एक आम रिट याचिका दायर की थी। जबकि उनमें से कुछ ने धारा 25 (6) के साथ पठित धारा 28 (2) के तहत जारी नोटिस पर सवाल उठाते हुए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। उत्तराखंड वैट अधिनियम, कुछ अन्य लोगों ने मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश पर सवाल उठाया था, जिसमें विषय लेनदेन को उत्तराखंड वैट अधिनियम की धारा 3 (10) (बी) के तहत कर के लिए योग्य एक अंतर-राज्य खरीद माना गया था।

2. तथ्य यह है कि सभी याचिकाकर्ता उत्तराखंड राज्य के बाहर व्यापार करने वाले पंजीकृत डीलर हैं। हालाँकि, उन्होंने अपने कमीशन एजेंटों के माध्यम से, उत्तराखंड राज्य के भीतर किसानों/ किसानों से मेंथ ऑयल की खरीद की। चूंकि अपीलकर्ताओं, इन चार अपीलों में, मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन के अधीन नहीं थे, और उन्होंने नोटिस पर सवाल उठाते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया है, हमारे लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश की सामग्री पर ध्यान देना अनावश्यक है ।

3. अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं ने अपने कमीशन एजेंटों के माध्यम से राज्य में कृषकों/ किसानों से मेंथा तेल और पेपरमिंट तेल खरीदा। उत्तराखंड के. यह उनका मामला था, उनके द्वारा दायर रिट याचिका में, कि, उनके द्वारा अपने कमीशन एजेंटों के साथ निष्पादित समझौते के संदर्भ में, एजेंटों को प्रचलित बाजार दर पर मेंथा तेल की निर्दिष्ट मात्रा खरीदने की आवश्यकता थी, जैसा कि सूचित किया गया था। समय-समय पर, प्रधान के लिए और उसकी ओर से कृषकों, कृषकों आदि से 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कमीशन के आधार पर, और प्रधान के निर्देशों के अनुसार उसे प्रधान के गंतव्य तक भेजना; और प्रिंसिपल को आवश्यकता के अनुसार उक्त खरीद के बदले कमीशन एजेंट को बैंक ड्राफ्ट, बैंक हस्तांतरण के माध्यम से अग्रिम रूप से एकमुश्त भुगतान करना था।

4. जिस समझौते पर अपीलकर्ता भरोसा करते हैं, उसमें प्रिंसिपल को उपर्युक्त तेल भरने के लिए कमीशन एजेंटों को खाली ड्रम आदि उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता होती है; यदि प्रिंसिपल के पास ड्रम उपलब्ध नहीं थे, तो एजेंट को प्रिंसिपल की ओर से ड्रम खरीदने और उपर्युक्त तेल भरने के बाद उसे प्रिंसिपल को भेजने की आवश्यकता थी; प्रिंसिपल इसके लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था; प्रिंसिपल को माल के बीमा, माल ढुलाई, लोडिंग और अनलोडिंग, भाराई मजदूरी, परीक्षण और जीएलसी शुल्क सहित सभी खर्चों के खिलाफ भुगतान करना भी आवश्यक था; जहां भी आवश्यक हो, ड्रमों को सील करने का खर्च, स्टेंसिलिंग और अन्य विविध खर्च और अन्य आकस्मिक खर्च और कमीशन जिसका उल्लेख कमीशन एजेंटों द्वारा जारी डिस्पैच नोट/ चालान में किया जाना था; और समझौते में उल्लिखित तेल की मात्रा को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

5. अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि विषय लेनदेन केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 3 (ए) के दायरे में आता है क्योंकि प्रिंसिपल की ओर से कमीशन एजेंटों द्वारा माल की खरीद की गई थी। एक अंतर-राज्य खरीद; और चूंकि माल राज्य के बाहर किसी स्थान पर पहुंचने के लिए चला गया, इसलिए उस पर उत्तराखंड वैट अधिनियम की धारा 3(10)(बी) के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है।

6. अपील के तहत आदेश में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए, कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहिए, और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ समझाना चाहिए और यह स्थापित करना चाहिए कि बिक्री वास्तव में एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी। और अंतर-राज्य बिक्री नहीं; और इसलिए, वे उत्तराखंड वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने राय दी कि यह प्रश्न, कि क्या कोई विशेष बिक्री अंतर-राज्य बिक्री थी या अंतर-राज्य बिक्री, तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है, और यह उचित था कि यह प्रश्न पहले मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था। स्वयं, याचिकाकर्ताओं को उनके प्रत्येक मामले में सुनने के बाद। याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के लिए मामला कर निर्धारण प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया। पहले पारित अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया गया था, और याचिकाकर्ताओं को आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई थी; और, तब तक, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया कि याचिकाकर्ता सभी दलीलें और दलीलें रखने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि उन्होंने रिट याचिका में न्यायालय के समक्ष किया था। अपने मामले का समर्थन करने के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष। इससे व्यथित होकर वर्तमान अपील करता है।

7. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 2014 के एसपीए नंबर 54 में अपने आदेश दिनांक 14.3.2014 द्वारा अपील के तहत फैसले और आदेश पर रोक लगा दी; और पक्षों को अपील पर सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। डिवीजन बेंच द्वारा पारित अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप, मूल्यांकन प्राधिकारी ने उत्तराखंड वैट अधिनियम की धारा 25(6) के साथ पठित धारा 28(2) के तहत उनके द्वारा जारी नोटिस के अनुसार कोई आगे कार्रवाई नहीं की है।

8. हमसे पहले श्री एस.के. अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील पोस्टी ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 5.7.2013 का नोटिस उन प्रिंसिपलों को संबोधित किया गया था, जो सभी उत्तराखंड राज्य के बाहर व्यवसाय कर रहे थे; वैट अधिनियम की धारा 3 चार्जिंग धारा है, और इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए; धारा 3(1) के तहत, यह केवल राज्य के भीतर की गई बिक्री है, जिस पर वैट अधिनियम के तहत कर लगाया जा सकता है; धारा 3(2) पंजीकृत डीलरों और पंजीकृत होने योग्य डीलरों से संबंधित है; चूँकि अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता राज्य के भीतर कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, वे पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, और इस प्रकार धारा 3(2) का उनके मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है; धारा 3(3) में कर योग्य टर्नओवर पर राज्य के भीतर सभी बिक्री पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता है; धारा 3(9)(बी)(बी)(i) के संदर्भ में, अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री को कर योग्य

टर्नओवर से बाहर रखा जाना आवश्यक है; याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने कमीशन एजेंटों के माध्यम से खरीदा गया तेल उन कृषकों/ किसानों से है जो डीलर नहीं हैं और प्रावधान के आलोक में उत्तराखंड वैट अधिनियम के दायरे में आते हैं। उसकी धारा 2(11); धारा 3(10)(बी) का खंड (1) केवल उन मामलों में लागू होगा जहां माल अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान नहीं बेचा जाता है; वर्तमान मामले में, माल सीएसटी अधिनियम की धारा 3 (ए) के दायरे में आने वाले अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान बेचा और खरीदा गया था; कोई भी कार्रवाई जो निर्धारण प्राधिकारी कर सकता था वह केवल सीएसटी अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में थी, न कि उत्तराखंड वैट अधिनियम की धारा 3(10)(बी) के तहत; वर्तमान मामले में, चूंकि विक्रेता (किसान/ किसान) एक अपंजीकृत डीलर है, और खरीदार (अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता) राज्य के बाहर स्थित है, बिक्री/ खरीद का लेनदेन अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान होता है; अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं ने राज्य के बाहर ले जाने के इरादे से सामान खरीदा; बिक्री का लेन-देन राज्य के बाहर पूरा हुआ, और सीएसटी अधिनियम की धारा 3(ए) के दायरे में आता है; परिणामस्वरूप, कर केवल सीएसटी अधिनियम की धारा 6 के तहत लगाया जा सकता है, न कि उत्तराखंड वैट अधिनियम की धारा 3(10) के तहत; कृषकों/ किसानों को पता था कि उन्होंने माल उन खरीदारों को बेच दिया है जो राज्य के बाहर से थे, और वे माल राज्य के बाहर ले जाएंगे; इससे यह लेन-देन एक अंतर-राज्यीय बिक्री बन जाएगा; यदि क्रेता माल को राज्य के बाहर ले जाने के इरादे से माल खरीदता है, तो यह अंतर-राज्य बिक्री के समान होगा, और विक्रेता का इरादा पूरी तरह से अप्रासंगिक है; धारा 3(10) के प्रावधान के अनुसार, मूल्यांकन प्राधिकारी केवल कमीशन एजेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं; जबकि कमीशन एजेंट कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उस पर लगाए गए कर, यदि कोई हो, को प्रिंसिपल से वसूल कर सकता है, जिसने कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रिंसिपल को नोटिस जारी करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की है, जो राज्य के बाहर व्यापार कर रहा था, और उस पर उत्तराखंड वैट अधिनियम की धारा 3(10)(बी) के तहत कर लगाया जाएगा; धारा 3(डी) उ.प्र. व्यापार कर उत्तराखंड वैट अधिनियम की धारा 3(10) के अनुरूप है, और बिक्री कर आयुक्त, यूपी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में। वी. हनुमान ट्रेडिंग कंपनी, 1979 (43) एसटीसी 408, बिक्री कर आयुक्त, यूपी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि की गई। और अन्य बनाम मैसर्स बख्तावर लाल कैलाश चंद आढ़ती और अन्य, (1992) 3 एससीसी 750, आक्षेपित कारण बताओ नोटिस क्षेत्राधिकार के बिना है और रद्द किए जाने योग्य है।

9. विद्वान वकील श्री एस.के.पोस्टी, ए.पी. राज्य बनाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य, (2002) 5 एससीसी 203 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करेंगे; मैसर्स केल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, (1973) 2 एससीसी 551; और हैदराबाद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2011) 4 एससीसी 705 में अपनी दलील के समर्थन में कहा कि विषय लेनदेन सीएसटी

अधिनियम की धारा 3 (ए) के दायरे में आता है। वह महालक्समी राइस मिल्स और अन्य बनाम यूपी राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करेंगे। और अन्य (1998) 6 एससीसी 590, अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में कि, उत्तराखंड वैट अधिनियम की धारा 3(10)(बी) के प्रावधान के आलोक में, मूल्यांकन प्राधिकारी केवल कमीशन एजेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं, जो एक प्रिंसिपल है।

10. यह सवाल कि क्या लेनदेन अंतर-राज्यीय बिक्री है या अंतर-राज्यीय बिक्री, तथ्यों से असंबंधित कानून का शुद्ध प्रश्न नहीं है, बल्कि एक मिश्रित मामला है। तथ्य और कानून का प्रश्न. यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में पहली बार तथ्य के विवादित प्रश्नों की जांच नहीं करेगा, क्योंकि ये सभी मामले हैं जिनकी जांच शुरू में मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और उसके बाद, यदि आवश्यक हो, वैधानिक अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार हमेशा उन मामलों में लागू किया जा सकता है, जहां अन्य बातों के अलावा, शिकायत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की है या कि रिट याचिका में लगाया गया आदेश पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बिना है, यह सवाल कि क्या कार्यवाही क्षेत्राधिकार की कमी से ग्रस्त है, इस न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर जांच की जाएगी।

11. यह केवल तभी होता है जब मूल्यांकन प्राधिकारी अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता और उसके कमीशन एजेंट के बीच हुए समझौते की जांच से संतुष्ट हो जाता है कि उक्त समझौता वास्तविक है, तब वह निर्धारित शर्तों के आलोक में ऐसा कर सकता है। उक्त समझौता, यह निर्धारित करता है कि क्या कमीशन एजेंट द्वारा उत्तराखंड राज्य के भीतर कृषकों/ किसानों से तेल की खरीद का लेनदेन, जिसे राज्य के बाहर अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता को ले जाया जा रहा है, एक अंतर-राज्य बिक्री है या एक अंतर-राज्य बिक्री है। बिक्री करना।

12. जबकि, सरसरी तौर पर पढ़ने पर, हनुमान ट्रेडिंग कंपनी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, राज्य के बाहर व्यापार करने वाले प्रमुख की ओर से एक कमीशन एजेंट द्वारा माल की खरीद से भी संबंधित है, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हनुमान मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ट्रेडिंग कंपनी, जिसे बिक्री कर आयुक्त, यूपी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि की गई थी। और अन्य बनाम मैसर्स बख्तावर लाल कैलाश चंद आढ़ती और अन्य, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ बिक्री कर आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण पेश किया गया था, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश। बिक्री कर अधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अपील में बरकरार रखा गया था, लेकिन संशोधन में

इसे निर्धारिती के पक्ष में रखा गया था। जैसा कि इन आदेशों में उल्लेख किया गया है, तथ्यों के आधार पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रश्न की जांच की कि क्या लेनदेन धारा 3 (ए) के दायरे में आने वाला अंतर-राज्यीय लेनदेन था या नहीं। सीएसटी अधिनियम. हनुमान ट्रेडिंग कंपनी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियाँ पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की राय के लिए कानून के कुछ प्रश्नों का उल्लेख करने पर की गई थीं, न कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही में। भारत।

13. हनुमान ट्रेडिंग कंपनी के विपरीत, यहां अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं ने कारण बताओ नोटिस के खिलाफ सीधे इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया है और तर्क दिया है कि चूंकि, उनके अनुसार, लेनदेन अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान था, और उत्तराखंड वैट अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी एक अंतर-राज्य बिक्री/ खरीद नहीं थी, मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस, अधिकार क्षेत्र के बिना था।

14. इसके तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना हमारे लिए पूरी तरह से अनुचित होगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 226, तथ्य के प्रश्नों पर निर्णय देने के लिए, वह भी रिट कार्यवाही में पहली बार। सभी तर्क जो अब हमारे सामने रखे गए हैं, उन्हें अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष भी रखा जा सकता है। कराधान के मामलों में, उच्च न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करना अनुचित है, या तो कारण बताओ नोटिस के चरण में, या मूल्यांकन के चरण में, जहां वैकल्पिक उपाय के माध्यम से उत्तर दाखिल करना उपलब्ध है। [भारत संघ (यूओआई) बनाम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज: (2003) 5 एससीसी 194।]

15. कारण बताओ नोटिस जारी करने से यह माना जाता है कि प्रतिक्रिया पर विचार किया जाएगा और उसके बाद ही मामले पर निर्णय लिया जाएगा। इसलिए, कारण बताने के लिए कहा गया व्यक्ति के पास अधिकारियों को संतुष्ट करने का पूरा अवसर है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। (भारत संघ बनाम जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड: (1996) 10 एससीसी 520। कारण बताओ नोटिस जारी करने का उद्देश्य सुनवाई का अवसर प्रदान करना है और, एक बार कारण दिखाए जाने पर, यह विचार करने के लिए प्राधिकारी के लिए खुला है रखे गए तथ्यों और प्रस्तुतियों के आलोक में ही मामले पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। उस चरण से पहले अदालत द्वारा हस्तक्षेप समय से पहले होगा। (यूपी राज्य बनाम ब्रह्म दत्त शर्मा: एआईआर 1987 एससी 943; प्रभागीय वन अधिकारी बनाम एम. रामलिंगा रेड्डी (2007) 9 एससीसी 286)।

16. आमतौर पर, एक रिट अदालत कारण बताने के नोटिस पर सवाल उठाने वाली रिट याचिका पर विचार करने के लिए अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगी, जब तक कि ऐसा न हो। अन्य बातों के साथ-साथ, बिना अधिकार क्षेत्र के जारी किया गया प्रतीत होता है, (यूपी राज्य बनाम ब्रह्म दत्त शर्मा, विशेष निदेशक बनाम मोहम्मद गुलाम गौस: (2004) 3 एससीसी 440, भारत संघ बनाम कुनीसेट्टी सत्यनारायण: (2006) 12 एससीसी 28, कार्यकारी अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड बनाम रमेश कुमार सिंह: (1996) 1 एससीसी 327, उलगप्पा बनाम डिविजनल कमिश्नर, मैसूर: (2) 001) 10 एससीसी 639 और सीमेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य: (2006) 12 एससीसी 33), खासकर जब याचिकाकर्ता के पास अधिनियम के तहत एक प्रभावी उपाय है। (पंजाब राज्य बनाम भटिंडा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड: (2007) 11 एससीसी 363)। लेकिन ये न्यायालयों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में खुद पर लगाई गई सीमाएं हैं और ये क्षेत्राधिकार संबंधी कारकों के मामले नहीं हैं। (भारत संघ बनाम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज: (2003) 5 एससीसी 194)। आमतौर पर, यह उचित या उचित नहीं होगा कि अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्यों से निपटने के लिए प्राधिकरण/ न्यायाधिकरण के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दरकिनार कर दिया जाए और ऐसे प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय, उसके रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय के समक्ष मांगा जाए। (एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड बनाम वर्कर्स: एआईआर 1963 एससी 569, प्रभागीय वन अधिकारी बनाम एम. रामलिंगा रेड्डी)। हालाँकि, यदि कोई अन्य प्रभावी और प्रभावी उपाय उपलब्ध है, तो रिट याचिका पर विचार न करने के लिए उच्च न्यायालय पर स्व-लगाया गया प्रतिबंध एक बाधा के रूप में काम नहीं करेगा जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है। (व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार: (1998) 8 एससीसी 1)।

17. बहुत ही दुर्लभ और असाधारण मामलों में, उच्च न्यायालय कारण बताओ नोटिस को रद्द कर सकता है यदि यह पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बिना पाया जाता है। कारण बताओ नोटिस कार्रवाई के किसी भी कारण को जन्म नहीं देता क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता एक प्रतिकूल आदेश जो किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है। यह बहुत संभव है कि, कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करने के बाद, संबंधित प्राधिकारी कार्यवाही बंद कर सकता है और/ या यह मान सकता है कि आरोप स्थापित नहीं हुए हैं। कारण बताओ नोटिस किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसा तभी होता है जब कोई अंतिम आदेश, अन्यथा किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, पारित किया जाता है, तभी कहा जा सकता है कि उक्त पक्ष को कोई शिकायत है। (भारत संघ बनाम कुनीसेट्टी सत्यनारायण)।

18. दूसरी ओर, जहां पूर्वाग्रहपूर्ण कार्रवाई की धमकी पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है, किसी व्यक्ति को अदालत की सुरक्षा मांगने से पहले उसे होने वाली चोट की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा जा

सकता है। हालाँकि, यदि प्राधिकारी के पास कारण बताओ नोटिस जारी करने की कानून में शक्ति है, तो कारण बताने के लिए कहा गया व्यक्ति नोटिस के चरण में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए खुला नहीं होगा। (सेना प्रमुख बनाम मेजर धर्मपाल कुकरेती: (1985) 2 एससीसी 412)।

19. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि कारण बताओ नोटिस में दिए गए तथ्यों को सही न मानते हुए, कारण बताओ नोटिस, पूर्व दृष्टया, क्षेत्राधिकार के बिना हो, (यूपी राज्य बनाम अनिल कुमार रमेश चंद्र ग्लास वर्क्स: (2005) 11 एससीसी 451), यानी, नोटिस प्रथम दृष्टया 'शून्यता' है ' या कानून की नजर में तथ्यों की जांच करने के लिए प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र की पूर्ण कमी या उस अभिव्यक्ति के पारंपरिक अर्थ में पूरी तरह से "क्षेत्राधिकार के बिना" - यानी, यहां तक कि कार्यवाही की शुरुआत या शुरुआत, इसके चेहरे पर, और कुछ भी अधिक के बिना, पूरी तरह से है अनाधिकृत. अन्य सभी मामलों में, यह उचित ही है कि पार्टी संबंधित प्राधिकारी के समक्ष कारण बताए और उसमें क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति उठाए। (बिहार राज्य आवास बोर्ड बनाम रमेश कुमार सिंह, विशेष निदेशक बनाम मोहम्मद गुलाम गौस, प्रभागीय वन अधिकारी बनाम एम. रामलिंगा रेड्डी)।

20. याचिकाकर्ता द्वारा केवल यह दावा करना कि कोई नोटिस क्षेत्राधिकार के बिना है, पर्याप्त नहीं होगा। प्रथम दृष्टया ऐसा ही स्थापित होना चाहिए। जहां तथ्यात्मक निर्णय आवश्यक हो, वहां हस्तक्षेप को आमतौर पर खारिज कर दिया जाता है। (भारत संघ बनाम विक्को प्रयोगशालाएँ: (2007) 13 एससीसी 270)। क्या कारण बताओ नोटिस किसी कानूनी आधार पर स्थापित किया गया है, यह एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है जिस पर नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा आग्रह किया जा सकता है और ऐसे मुद्दों पर, पीड़ित व्यक्ति के अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा शुरू में निर्णय भी लिया जा सकता है। (विशेष निदेशक बनाम मोहम्मद गुलाम घोष; प्रभागीय वन अधिकारी बनाम एम. रामलिंगा रेड्डी)।

21. विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के उपाय से वंचित कर दिया है। अंतर-न्यायालय अपील में हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब अपील के तहत आदेश पेटेंट अवैधता से ग्रस्त हो। अपील के तहत आदेश ऐसी किसी भी कमज़ोरी से ग्रस्त नहीं है। नतीजतन, अपीलें विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं। हालाँकि, परिस्थितियों में, बिना किसी लागत के।

22. चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित समय पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए यह अनुमति देने के लिए पर्याप्त है अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं को आज से 30 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। यदि वे उपरोक्त अवधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करते हैं, तो मूल्यांकन प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करेगा और कानून के अनुसार एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा। जब तक मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा ऐसे आदेश पारित नहीं किए जाते, तब तक कारण बताओ नोटिस पर अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं का जवाब प्राप्त होने पर, कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित राशि की वसूली के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, यदि अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता आज से 30 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो मूल्यांकन प्राधिकारी आगे बढ़ने और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए खुला है, इसके बाद अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ताओं के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना।

23. इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति सामान्य शुल्क के भुगतान पर 26.3.2019 तक पार्टियों के विद्वान वकील को प्रस्तुत की जाए।

(एन.एस. धनिक, जे.) (रमेश रंगनाथन, सी.जे.)

19.03.2019

नाहिद